प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
DEPARTMENT OF
ADMINISTRATIVE REFORMS &
PUBLIC GRIEVANCES

GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय सुधार

क) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना

ख) ई-ऑफिस

ग) स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी

मासिक रिपोर्ट | अगस्त 2025

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

विषय सूची

1. मुख्य- मुख्य बातें, अगस्त 2025.....1

I. ई ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन.....1

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियाँ (अगस्त, 2025)... 2

III. लंबित मामलों में कमी 2

2. औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग).....3

2.1 डिलेयरिंग प्रवृत्ति (अगस्त 2025)... 3

2.2 डिलेयरिंग की स्थिति 4

3. ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन.....6

3.1 ई-ऑफिस विश्लेषण 6

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी 7

3.3 ई-फाइल सृजन 8

3.4 अंतर विभागीय फ़ाइल संचलन 8

3.5 ई-रिसीट अपनाना (ई-रिसीट का % शेयर).....9

3.5 ई-ऑफिस विश्लेषण.....10

4. विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना ... .13

4.1कुल अर्जित राजस्व 14

4.2 स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (अगस्त 2025)... 15

4.3 खाली हुआ स्थान (अगस्त 2025).....15

क . शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व.....16

4.4 स्वच्छता अभियान स्थल (अगस्त 2025)... 17

4.5 छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (अगस्त 2025).....17

5. पहले- बाद में 18

6. सर्वश्रेष्ठ परिपाटियाँ- कार्यालय स्थान का कुशल प्रबंधन 20

7. मंत्रालयों/विभागों का मापदंड - वार कार्य निष्पादन 21

8. इन फोकस : पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 23

क. परिचय..... 23

ख. झलकियाँ 23

ग. उल्लेखनीय उपलब्धियां 26

9. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन 27

10. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन 28

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन.....30

अनुलग्नक I : अपलोड नहीं किए गए आँकड़े.....32

अनुलग्नक II: संकेताक्षरों की सूची 33

1

मुख्य-मुख्य बातें
अगस्त 2025

I. ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन

64

मंत्रालयों/विभागों के पास कम से कम 90 प्रतिशत ई-फ़ाइलें हैं

19

मंत्रालयों/विभागों के पास की 100 प्रतिशत ई-रिसीट्स हैं

21

मंत्रालयों/विभागों का औसत ट्रांजैक्शन स्तर 4 अथवा 4 से कम है

ई-फाइलों का उपयोग (%)

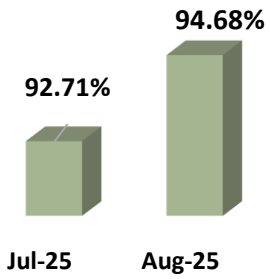

अगस्त 2025: 5,19,280 रिसीट्स में से 4,93,359 ई-रिसीटस थीं

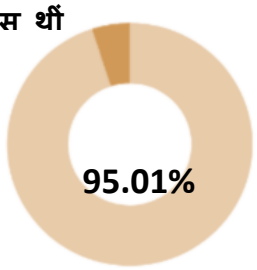

औसत ट्रांजैक्शन स्तर

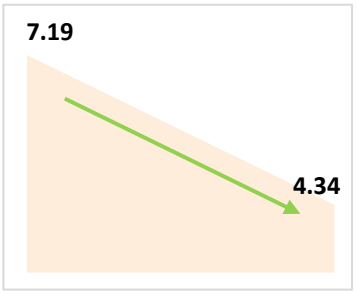

सक्रिय,बंद की गई और कुल ई-फ़ाइलों के मासिक आँकड़े

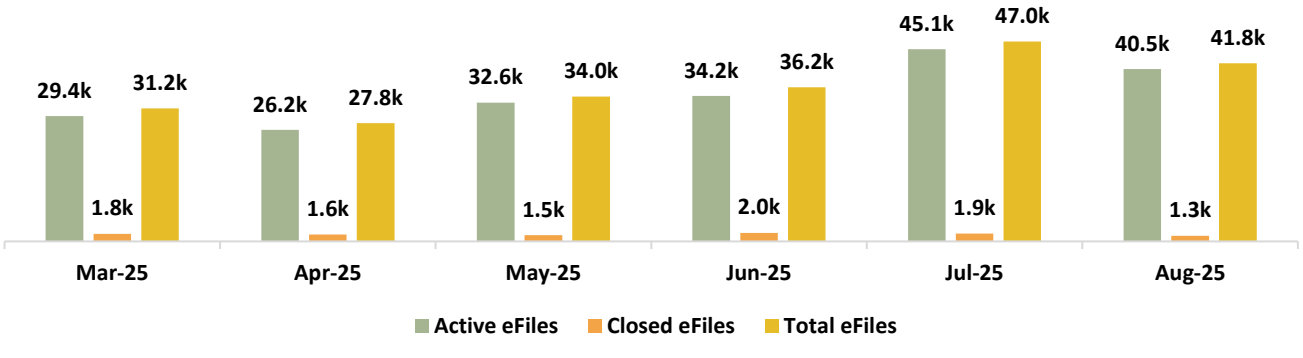

II. स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां (अगस्त 2025)

5,545 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया

4,78,299

वर्ग फुट स्थान खाली हुआ

74,44,00,730

स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व

III. लंबित मामलों में कमी

निपटान

- ✓ 4,37,813 लोक शिकायतें
- ✓ 16,716 लोक शिकायत अपीलें
- ✓ 1,216 संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र
- ✓ 242 राज्य सरकारों से प्राप्त पत्र
- ✓ 110 आईएमसी पत्र
- ✓ 394 पीएमओ से प्राप्त पत्र

पूरे किए गए संसदीय आश्वासन

81

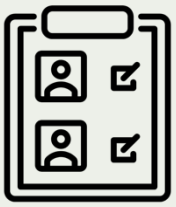

रिकॉर्ड प्रबंधन

62,811 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई और **34,681** फाइलों की छंटाई की गई।

2 औसत विशिष्ट स्तरों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण (डिलेयरिंग)

मुख्य व्याख्या

केंद्रीय सचिवालय में सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 2021 के 7.19 से घटकर अगस्त 2025 में केवल 4.34 रह गया है, जिससे प्रक्रियाएं

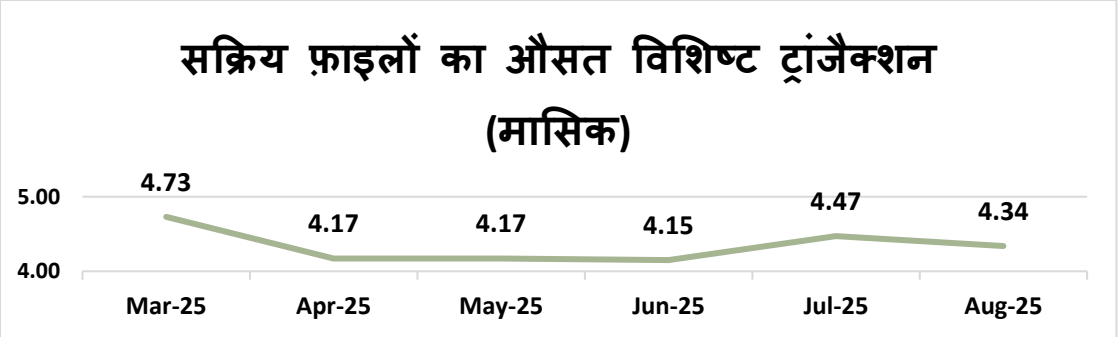

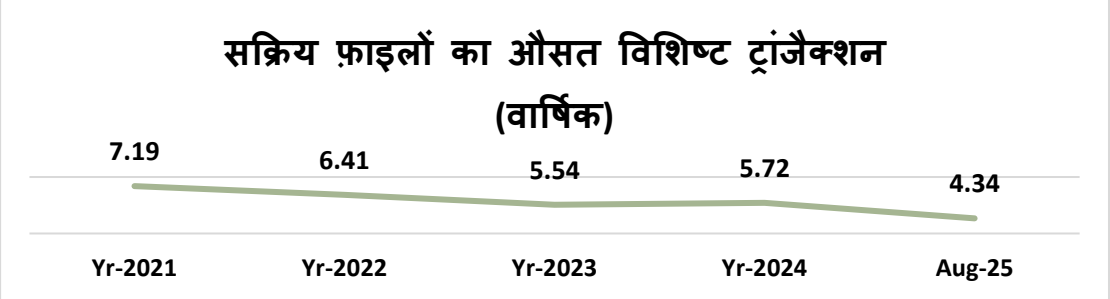

2.1 डिलेयरिंग प्रवृति (अगस्त 2025)

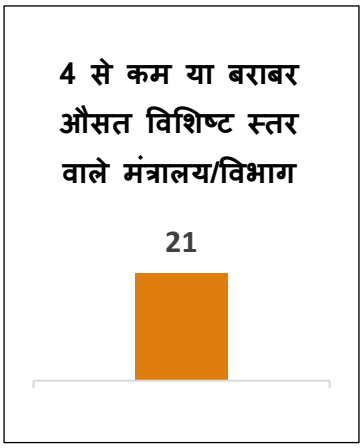

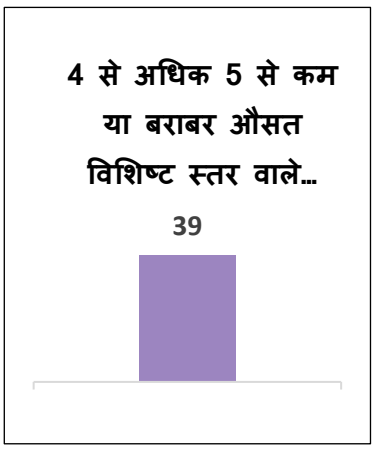

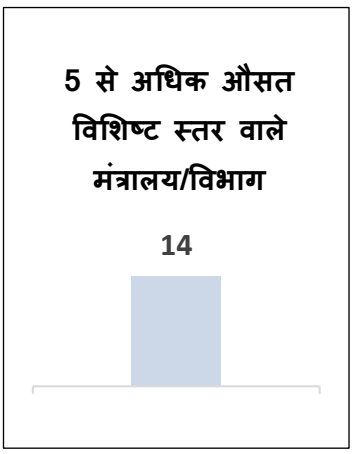

2.2 डिलेयरिंग की स्थिति

निम्नलिखित ग्राफ अगस्त 2025 के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तरों को दर्शाता है:

क. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर ≤ 4 तक है

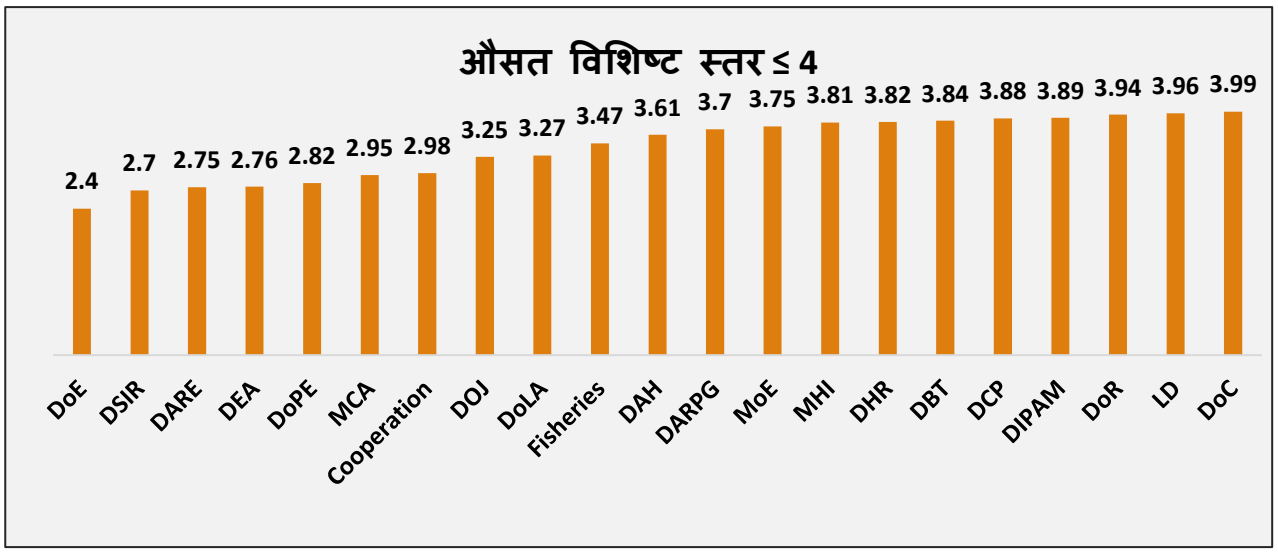

ख. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है

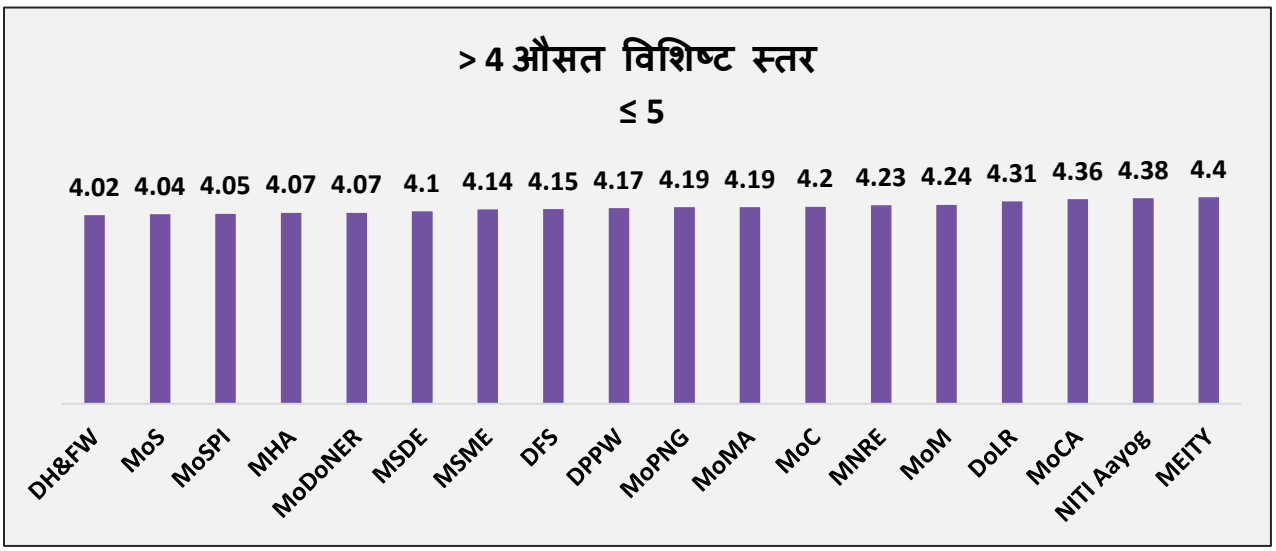

ग. ऐसे मंत्रालय/विभाग जिनका औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 4 से अधिक और 5 से कम या बराबर है

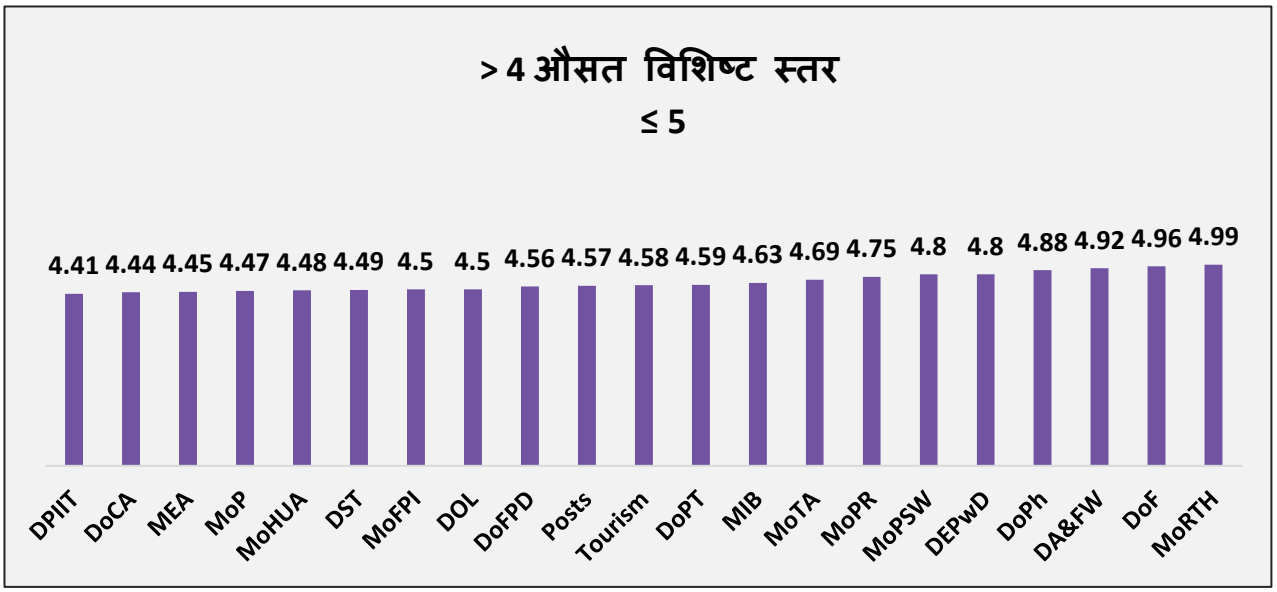

घ. 5 से अधिक औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर वाले मंत्रालय/विभाग >

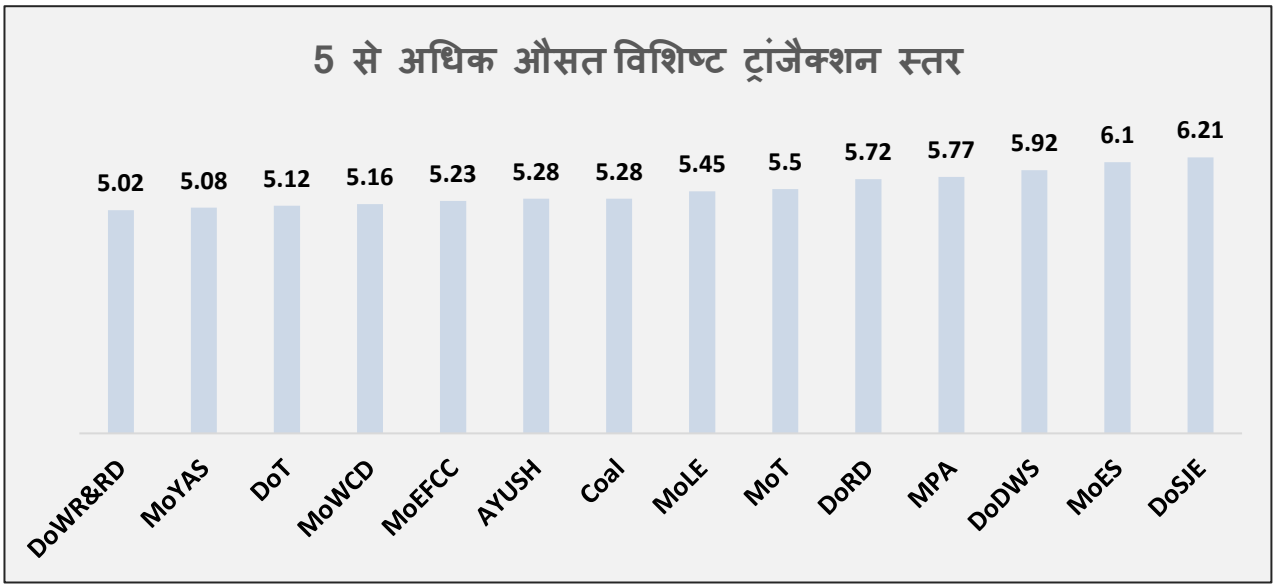

3 ई-ऑफिस विश्लेषण और कार्यान्वयन

3.1 ई-ऑफिस विश्लेषण

ई-ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड (https://vishleshan.eoffice.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को किया गया ।

यह डैशबोर्ड निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- गहन डाटा विश्लेषण को आसान बनाने और निर्णयन प्रकिया को सदृढ़ करने के लिए रियल टाइम मीट्रिक्स
- डाटा विजुअलाइज़ेशन और ट्रेंड के मूल्यांकन के माध्यम से निर्णयन प्रकिया मे वद्धि
- ई-ऑफिस को और अधिक सुव्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के डाटा विश्लेशष
- आईईडीएम के प्रभावी तथा व्यापक कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

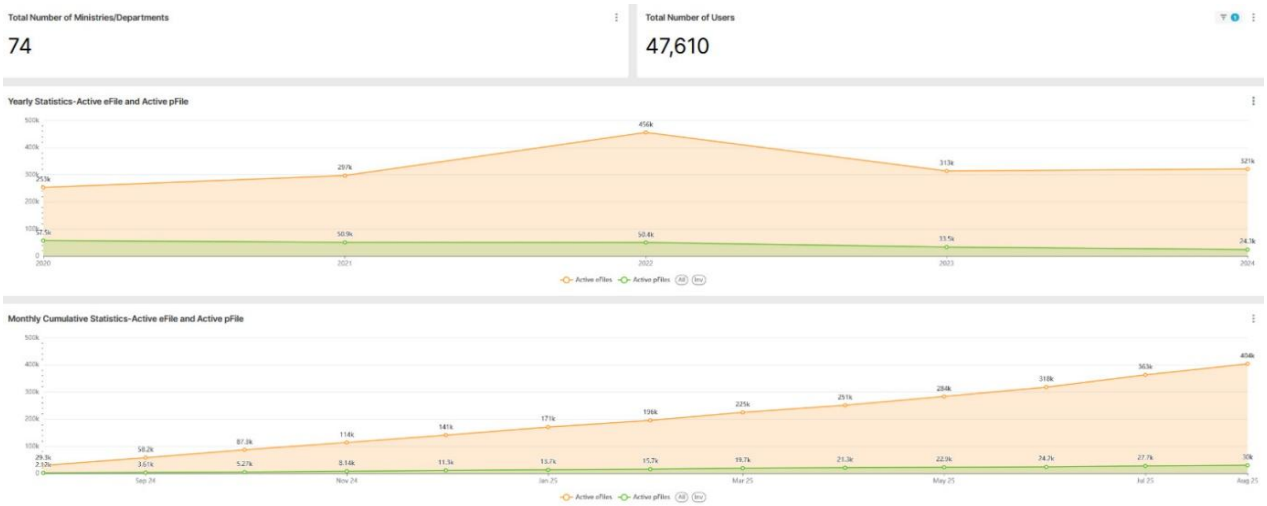

ई-ऑफिस विश्लेषण डैशबोर्ड इंटरफ़ेस

यूआरएल: https://vishleshan.eoffice.gov.in/

डैशबोर्ड केवल एनआईसी नेट पर उपलब्ध है। वर्तमान में यह भारत सरकार के सभी सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (जिनके संबंध में केवल एनआईसी ईमेल) और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ एनआईसी से विशिष्ट अनुरोध किया जाना है) के लिए सुलभ है।

3.2 ई-फाइल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी

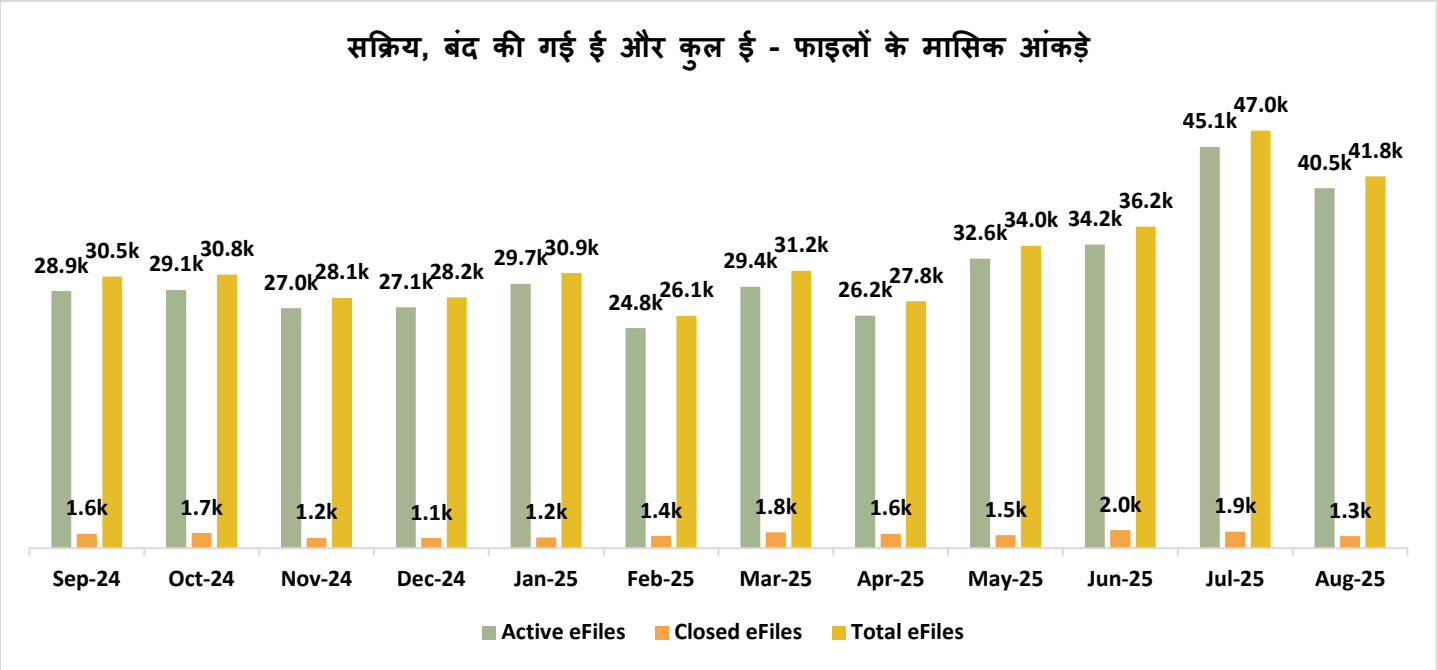

कुल ई-फाइलें सितंबर 2024 में 30.5 हजार से अगस्त 2025 में 41.8 हजारतक पहुंच गई हैं। यह मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निरंतर अपनाए जाने और सक्रिय उपयोग को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय और बंद की गई फाइलों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है - जो ***बेहतर डिजिटल वर्कफ़्लो और फ़ाइल प्रबंधन को दर्शाता है।***

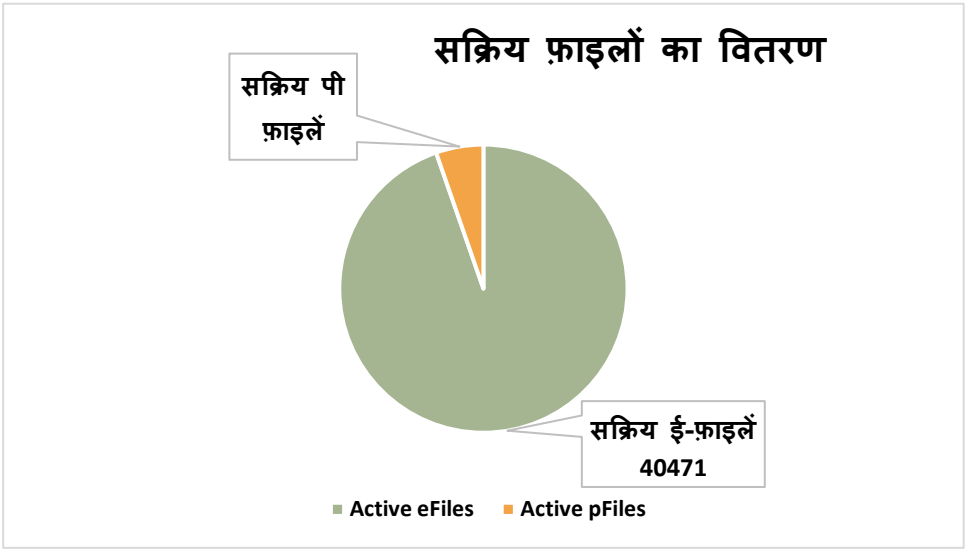

अगस्त, 2025 में कुल सक्रिय फाइलों में ई-फाइलों का हिस्सा **94.68%** था , जो फिजिकल फाइलों की तुलना में डिजिटल फाइलों के अधिक उपयोग को दर्शाता है।

3.3. ई-फ़ाइलों का सृजन

अगस्त 2025 माह के लिए सक्रिय ई-फाइलों में <90 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले मंत्रालय/विभाग:

क्र सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	ई-फ़ाइलों का %शेयर
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	89.72%
2	संस्कृति मंत्रालय	87.00%
3	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	86.07%
4	दूरसंचार विभाग	84.17%
5	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	83.23%
6	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	82.34%
7	आयुष मंत्रालय	79.15%
8	श्रम और रोजगार मंत्रालय	75.00%
9	गृह मंत्रालय	66.51%
10	राजभाषा विभाग	8.06%

3.4. अंतर-विभागीय फाइल संचलन

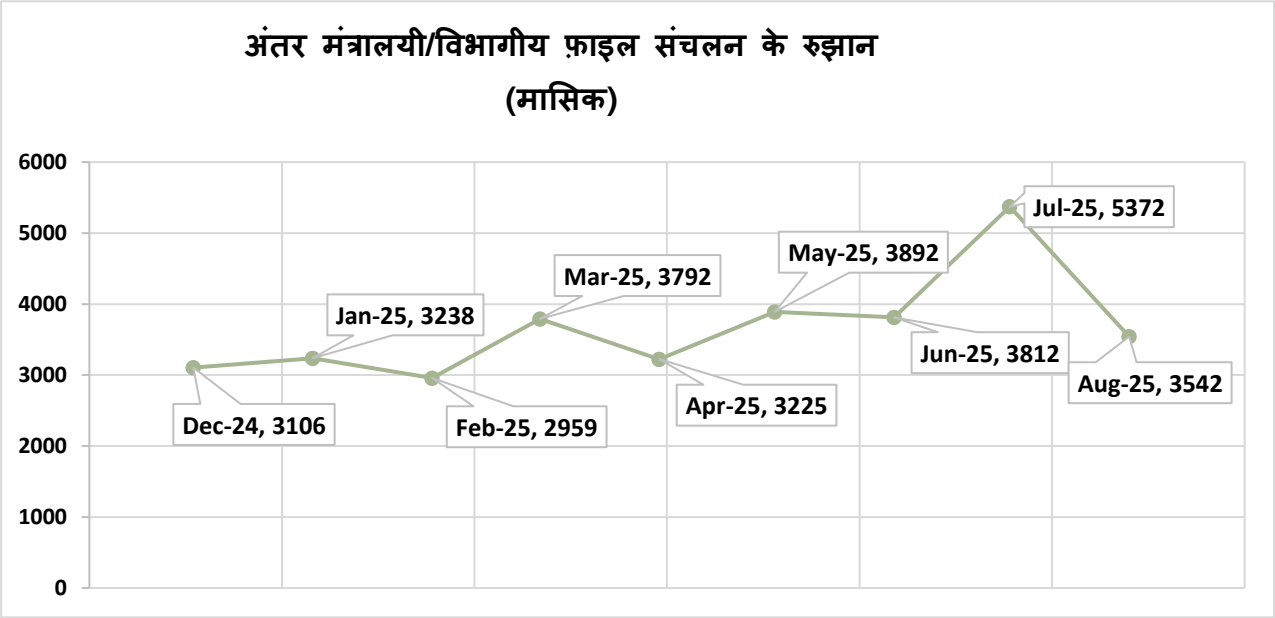

- **अंतर-मंत्रालयी फाइल संचलन में शीर्ष मंत्रालय/विभाग - अगस्त 2025**

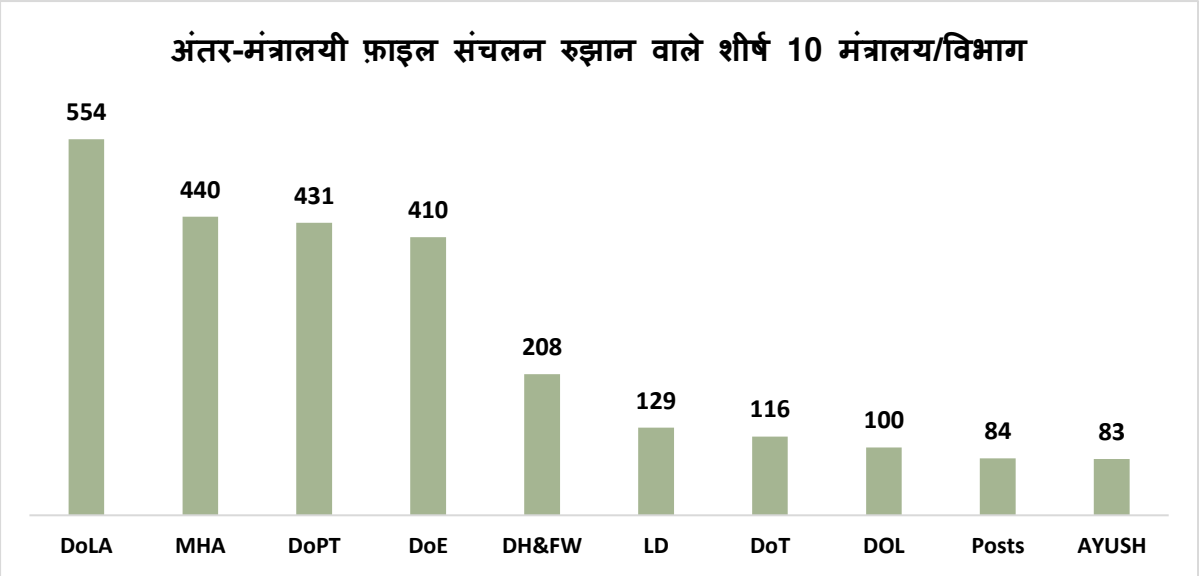

3.5. ई-रिसीट्स अपनाना (ई-रिसीट्स का % हिस्सा)

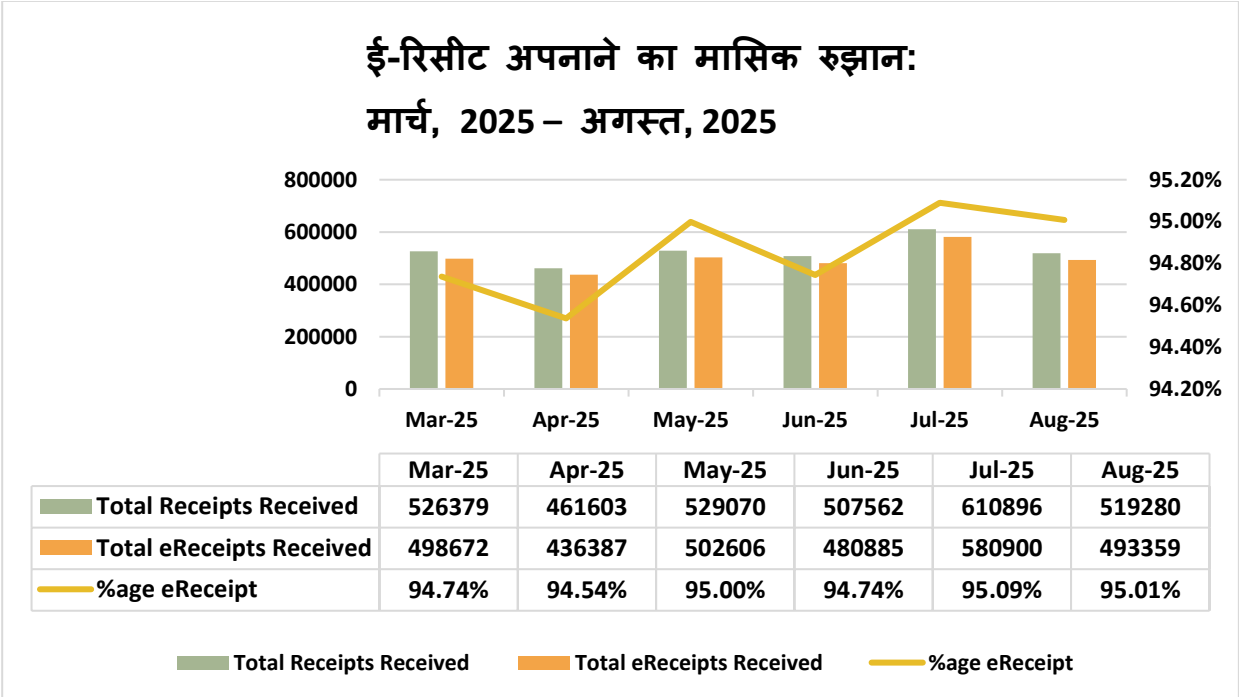

	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25
Total Receipts Received	526379	461603	529070	507562	610896	519280
Total eReceipts Received	498672	436387	502606	480885	580900	493359
%age eReceipt	94.74%	94.54%	95.00%	94.74%	95.09%	95.01%

पिछले छह महीनों में ई-रिसीट्स का शेयर लगातार 94% से ऊपर बना हुआ है, जो **अगस्त, 2025 में 95.01%** के उच्चतम स्तर पर है - यह मंत्रालयों/विभागों में रिसीट प्रबंधन में निरंतर डिजिटल अडॉपशन का संकेत है।

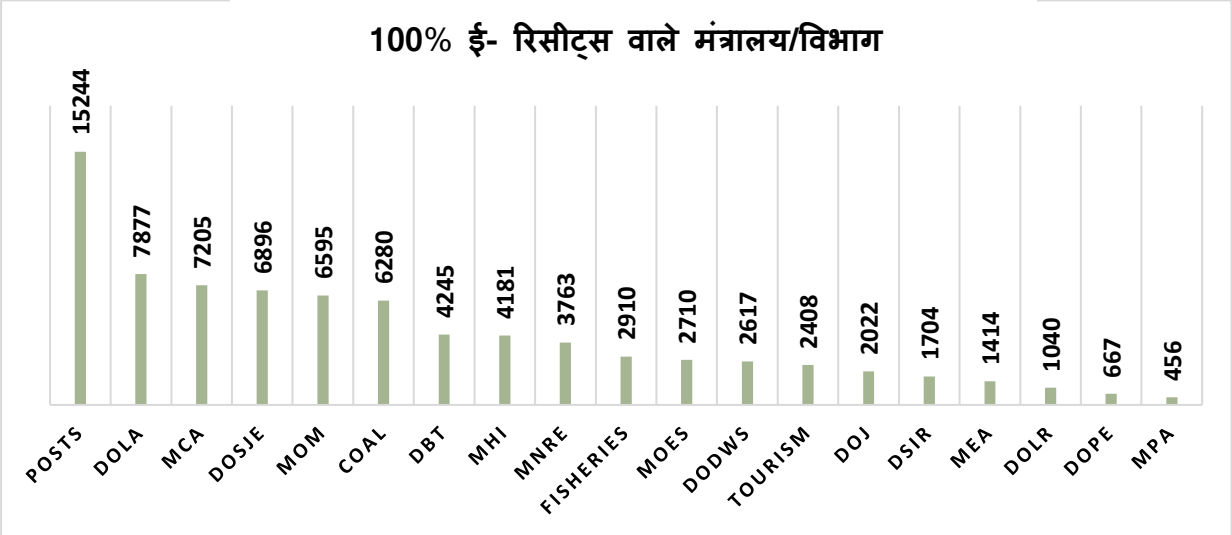

3.6. ई-ऑफिस विश्लेषण

अगस्त 2025 के लिए मंत्रालय-वार विश्लेषण संक्षेप में इस प्रकार है:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	% ई-रिसीट	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
1	डीईए - वित्त मंत्रालय	99.51%	94.76%	18.88%
2	डीओई - वित्त मंत्रालय	97.83%	79.03%	10.96%
3	शिक्षा मंत्रालय	92.96%	97.39%	36.84%
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	94.17%	93.32%	38.09%
5	विधि कार्य विभाग	100.00%	100.00%	12.3%
6	गृह मंत्रालय	66.51%	77.85%	33.28%
7	खान मंत्रालय	100.00%	100.00%	41.73%
8	विधायी विभाग	100.00%	99.80%	33.33%
9	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	89.72%	99.93%	43.23%
10	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	97.11%	98.46%	44.21%
11	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	86.07%	99.64%	55.92%
12	डाक विभाग	100.00%	100.00%	44.44%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	% ई-रिसीट	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
13	वाणिज्य विभाग	99.78%	97.19%	32.78%
14	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	99.53%	99.89%	34.21%
15	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.94%	48.05%
16	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	99.88%	98.49%	47.67%
17	डीओआर - वित्त मंत्रालय	98.57%	89.90%	28.87%
18	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	17.25%
19	पशुपालन और डेयरी विभाग	100.00%	99.81%	23.27%
20	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	94.93%	82.44%	47.91%
21	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	82.34%	89.84%	52.52%
22	डीएफएस - वित्त मंत्रालय	97.94%	94.17%	38.71%
23	दूरसंचार विभाग	84.17%	85.48%	55.22%
24	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	100.00%	99.97%	57.31%
25	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	100.00%	93.45%	36.19%
26	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	100.00%	99.85%	52.41%
27	श्रम और रोजगार मंत्रालय	75.00%	89.52%	64.37%
28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	100.00%	100.00%	65.31%
29	विदेश मंत्रालय	99.72%	100.00%	35.38%
30	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	99.16%	96.72%	37.58%
31	ग्रामीण विकास विभाग	100.00%	99.85%	66.18%
32	विद्युत मंत्रालय	96.06%	99.93%	45.96%
33	नीति आयोग	100.00%	98.38%	40.54%
34	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	100.00%	99.92%	44.7%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	% ई-रिसीट	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
35	नागर विमानन मंत्रालय	90.12%	99.70%	46.47%
36	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	100.00%	99.99%	61.23%
37	कोयला मंत्रालय	100.00%	100.00%	53.82%
38	सहकारिता मंत्रालय	91.58%	90.96%	13.99%
39	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	100.00%	100.00%	62.89%
40	वस्त्र मंत्रालय	99.57%	79.31%	56.18%
41	आयुष मंत्रालय	79.15%	79.94%	64.26%
42	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	100.00%	99.91%	51.39%
43	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	96.41%	98.87%	38.22%
44	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	96.60%	100.00%	35.71%
45	मत्स्य पालन विभाग	100.00%	100.00%	28.05%
46	पर्यटन मंत्रालय	99.49%	100.00%	50.83%
47	संस्कृति मंत्रालय	87.00%	96.41%	40.76%
48	उर्वरक विभाग	99.48%	99.84%	53.37%
49	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	100.00%	99.94%	50.9%
50	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	100.00%	85.32%	32.29%
51	डीएचआर विभाग - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	94.32%	89.66%	35.54%
52	पंचायती राज मंत्रालय	99.39%	99.92%	51.92%
53	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	100.00%	92.03%	53.19%
54	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	100.00%	99.63%	49.12%
55	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	100.00%	100.00%	1.68%
56	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	100.00%	99.93%	29.69%
57	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	83.23%	86.84%	43.97%

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सक्रिय ई-फाइलों का %	% ई-रिसीट	>4 विशिष्ट स्तर वाली फ़ाइलों का %
58	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00%	99.97%	54.47%
59	इस्पात मंत्रालय	92.91%	95.77%	42.4%
60	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	100.00%	100.00%	30%
61	उपभोक्ता मामले विभाग	93.85%	99.97%	49.47%
62	भारी उद्योग मंत्रालय	100.00%	100.00%	32.65%
63	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	100.00%	99.77%	24.36%
64	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.00%	100.00%	65.96%
65	औषध विभाग	100.00%	99.18%	51.52%
66	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	100.00%	98.69%	38.3%
67	न्याय विभाग	100.00%	100.00%	10%
68	भूमि संसाधन विभाग	100.00%	100.00%	44.44%
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	100.00%	100.00%	83.33%
70	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	100.00%	99.27%	5%
71	लोक उद्यम विभाग	100.00%	100.00%	9.09%
72	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	100.00%	98.41%	30%
73	दीपम - वित्त मंत्रालय	100.00%	99.90%	31.58%
74	राजभाषा विभाग	8.06%	16.67%	47.5%

जिन मंत्रालयों/विभागों में औसत विशिष्ट ट्रांजैक्शन स्तर 5 से अधिक है, उनके द्वारा डिलेयरिंग/डेलिगेशन की समीक्षा की जानी है।

4 विशेष अभियान और स्वच्छता को संस्थागत करना

कुल उपलब्धियां (2021 - अगस्त 2025)

मापदंड	एससी1.0 - एससी4.0	दिसंबर'24-जुलाई'25	अगस्त'25	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)	2,364.05	932.66	74.44	**3,371.15**
खाली हुआ स्थान (लाख वर्ग फुट में)	643.82	52.45	4.78	**701.05**
स्वच्छता अभियान स्थल	11,49,935	54,897	5,545	**1210377**
फाइलों की छंटाई (लाखों में)	131.4	6.46	0.35	**138.21**

आँकड़े विशेष अभियानों (एस.सी. 1.0 - एस.सी. 4.0) और सचिवालय सुधारों की निरंतर गति को दर्शाते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में सहायक हैं। अगस्त, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, संचयी उपलब्धियों में शामिल हैं: स्क्रैप निपटान से **₹33371.15** करोड़ की आय हुई, **701.05** लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ, **12.10** लाख से ज़्यादा स्थलों को स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत लाया गया और **138.21** लाख फाइलों का निपटान किया गया। दिसंबर, **2024** से अगस्त, **2025** तक हुई निरंतर प्रगति स्वच्छता के संस्थागतकरण और दैनिक शासन में दक्षता-उन्मुख परिपाटियों की पुष्टि करती है।

4.1.कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)

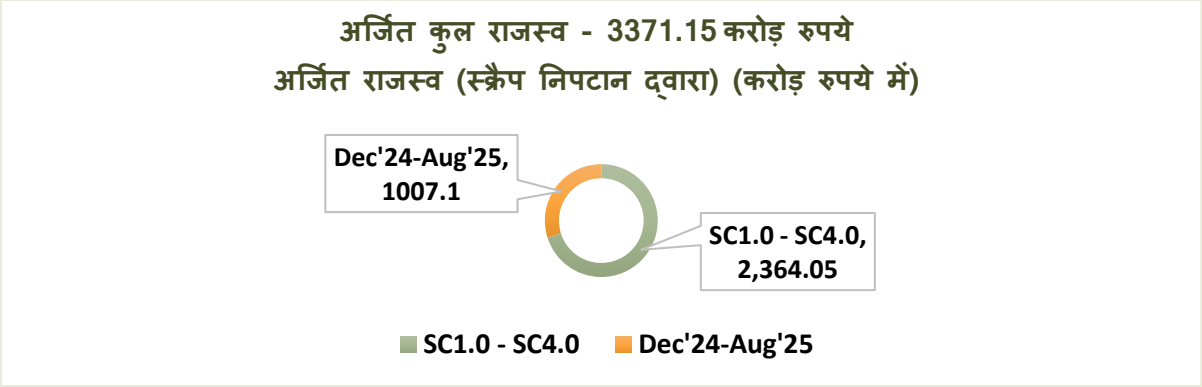

स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित कुल **₹3371.15 करोड़** राजस्व में से, **₹74.44** करोड़ अगस्त, 2025 और **1007.1** करोड़ रु. राजस्व के रूप में, **दिसंबर, 2024-जून 2025** के दौरान ही प्राप्त हुए, जो विशेष अभियान **एस. सी.1.0 - एस.सी. 4.0** से आगे निरंतर गति को दर्शाता है, जिसने पहले **₹2364.05 करोड़** की राशि का अंशदान किया था।

4.2. स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व (अगस्त 2025)

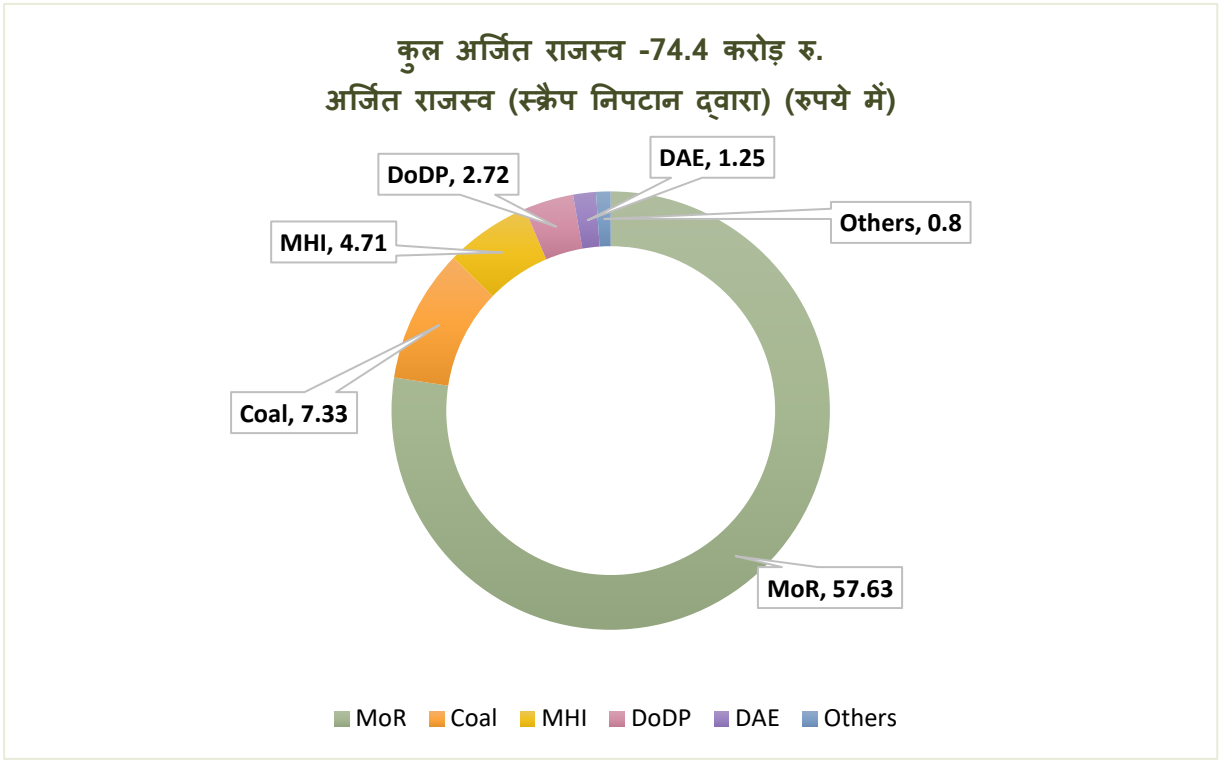

4.3. खाली हुआ स्थान (अगस्त 2025)

शीर्ष 5 मंत्रालयों/विभागों द्वारा खाली किया गया कुल स्थान (वर्ग फुट में) - **478299 वर्ग फुट**

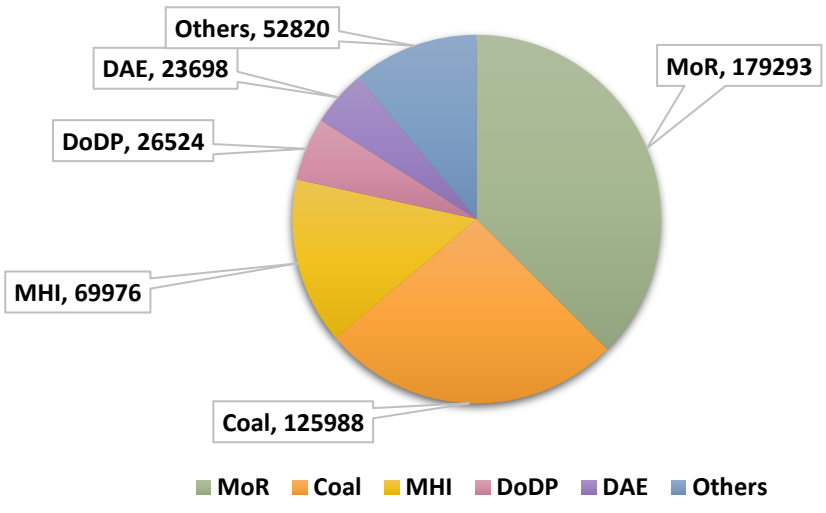

क. शीर्ष 3 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्क्रैप निपटान के माध्यम से अर्जित राजस्व

➢ रेल मंत्रालय: **अगस्त** 2025 **में अर्जित कुल राजस्व** 57,63,37,641 रु **है, अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 जोन इस प्रकार हैं**: -

क्र. सं.	क्षेत्र	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	पूर्वी रेलवे	30,00,00,000
2.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	12,78,46,889
3.	पश्चिम मध्य रेलवे	11,86,36,000

➢ **कोयला मंत्रालय:** अगस्त 2025 में अर्जित कुल राजस्व 7,32,86,879 रु है, अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 साइट इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	साइट/संगठन	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	बीसीसीएल	29600000
2.	एनसीएल	2720092
3.	ईसीएल	11419319

➢ **भारी उद्योग मंत्रालय:** अगस्त 2025 में अर्जित कुल राजस्व 4,70,99,471 रु. है, अर्जित राजस्व के अनुसार शीर्ष 3 साइट इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	साइट/कार्यालय	अर्जित राजस्व (रुपये में)
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2,98,04,074.9
2.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	69,69,871
3.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	64,27,452

4.4. स्वच्छता अभियान स्थल (अगस्त 2025)

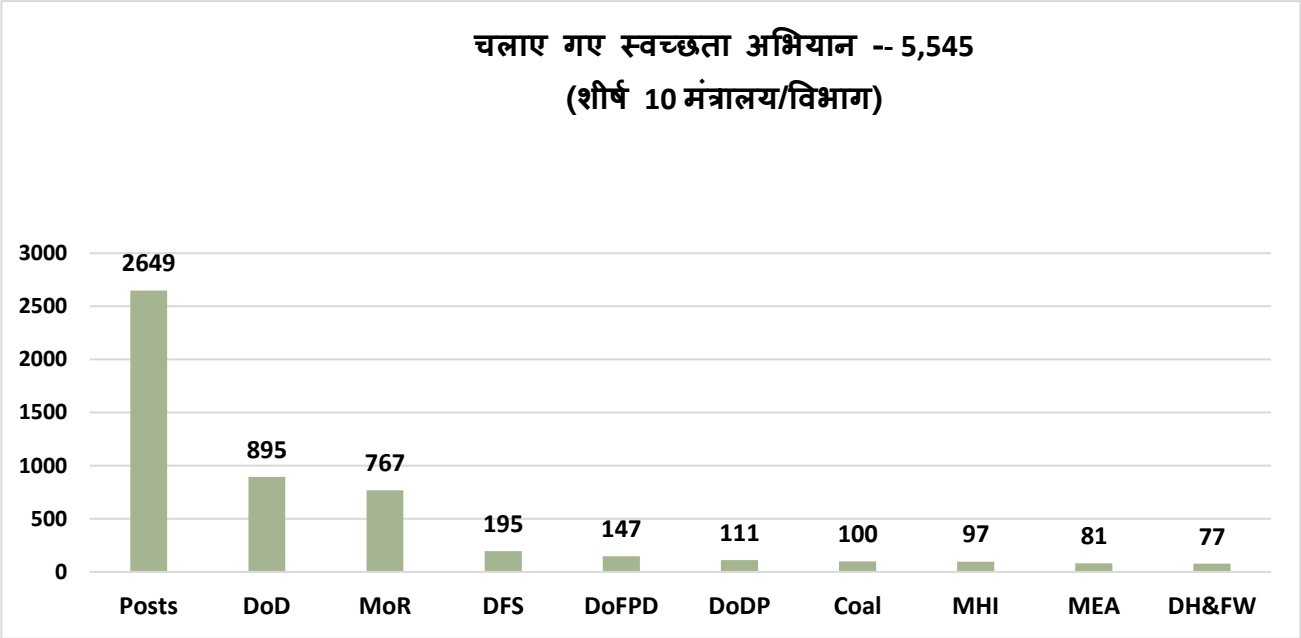

चलाए गए कुल 5,545 **स्वच्छता अभियानों** में से, अकेले **डाक विभाग ने कुल अभियानों का लगभग 50 प्रतिशत** अभियान चलाया, इसके बाद रक्षा विभाग, रेल मंत्रालय का स्थान है जो इन विभागों द्वारा स्वच्छता पहलों में मजबूत और निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

4.5. छँटाई की गई फिजिकल फाइलें (अगस्त 2025)

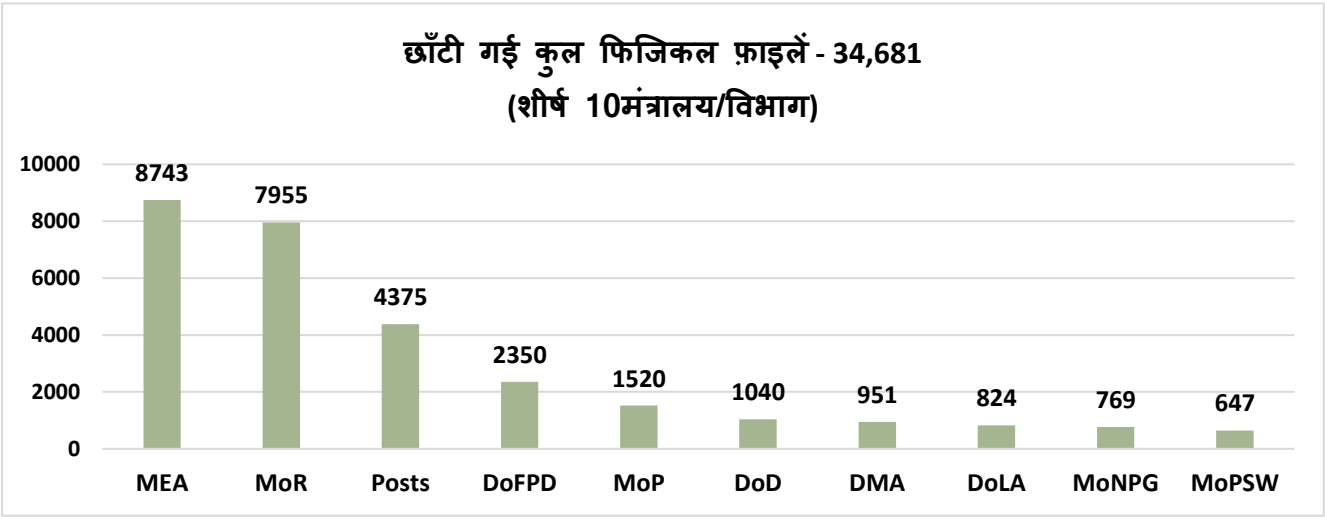

छंटाई की गई 34,681 फिजिकल फाइलों में से, विदेश मंत्रालय ने 8,743 फाइलों की छँटाई करके पहला स्थान प्राप्त किया इसके बाद रेल मंत्रालय और डाक विभाग का स्थान रहा। यह दर्शाता है कि प्रमुख मंत्रालय अव्यवस्था को दूर करने और फिजिकल फाइल प्रबंधन में सुधार लाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं।

5 पहले- बाद में

मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए सचित्र साक्ष्य-अगस्त 2025

पहले

बाद में

आयकर भवन, गुवाहाटी में वाहन पार्किंग के लिए स्क्रैप निपटान और स्थान का उपयोग; **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)**

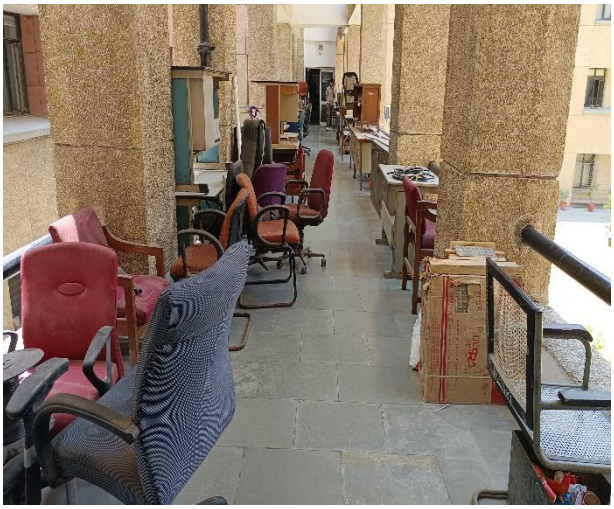

पहले

बाद में

ऐली की सफाई, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली, Meity

पहले

बाद में

अली यावर जंग नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), मुंबई में स्वच्छता अभियान चलाया गया; **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग**

पहले

बाद में

एआईआईएसएच, मैसूर में क्षेत्र की सफाई ; **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

पहले

बाद में

क्षेत्रीय संस्थान-II कार्यालय भवन, धनबाद, झारखंड में सीएमपीडीआई सेक्शन हॉल की सफाई ; **कोयला मंत्रालय**

6 कार्यालय स्थानों का कुशल प्रबंधन

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यालय स्थल की सफाई

परमाणु ऊर्जा विभाग के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला में खाली हुआ स्थान

7 मंत्रालयों/विभागों का मापदंड-वार कार्य-निष्पादन

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

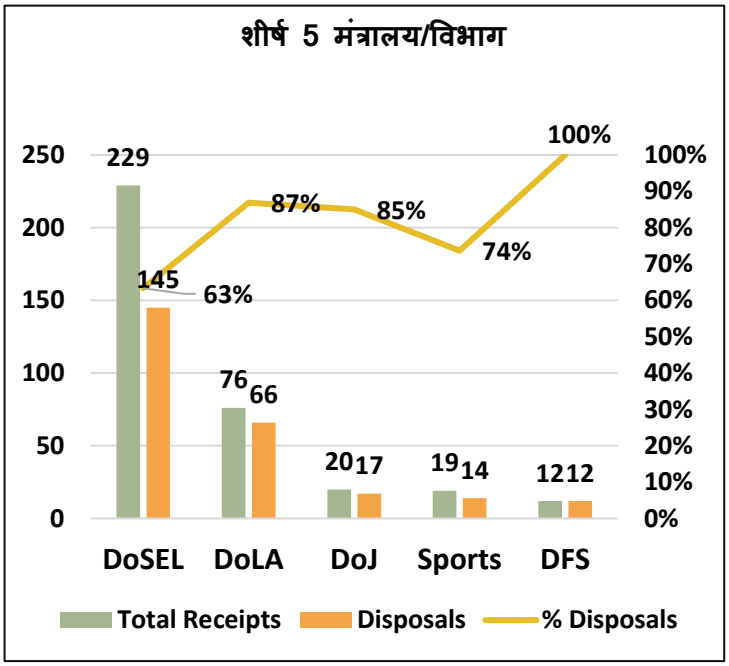

संसदीय आश्वासन

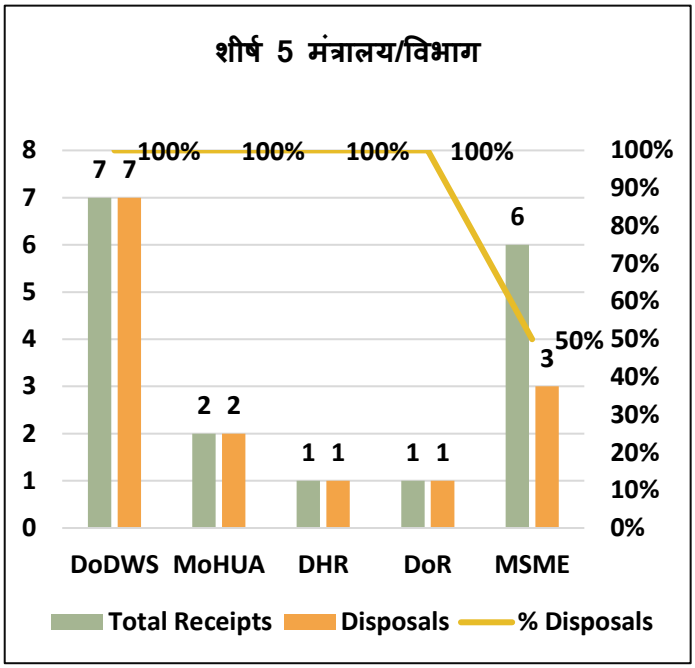

आईएमसी से प्राप्त पत्र

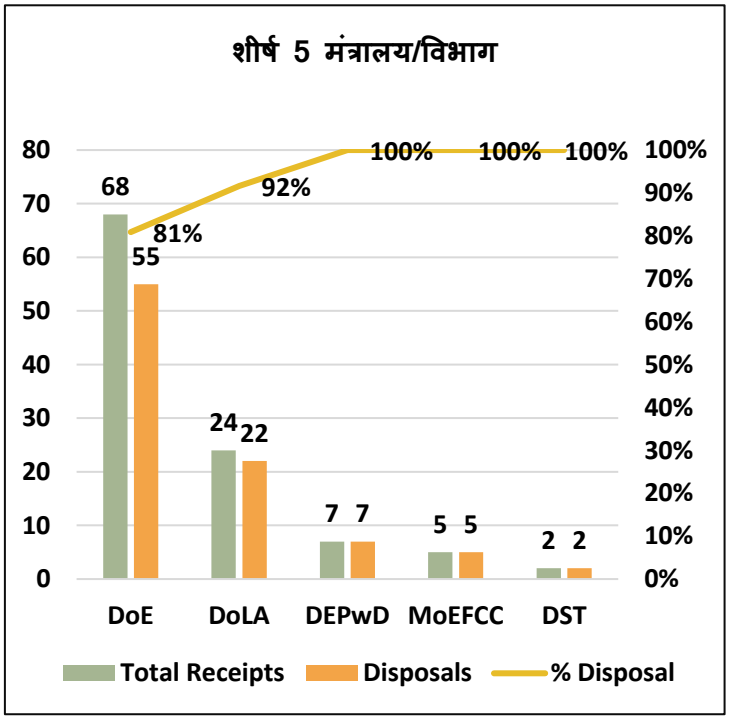

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र

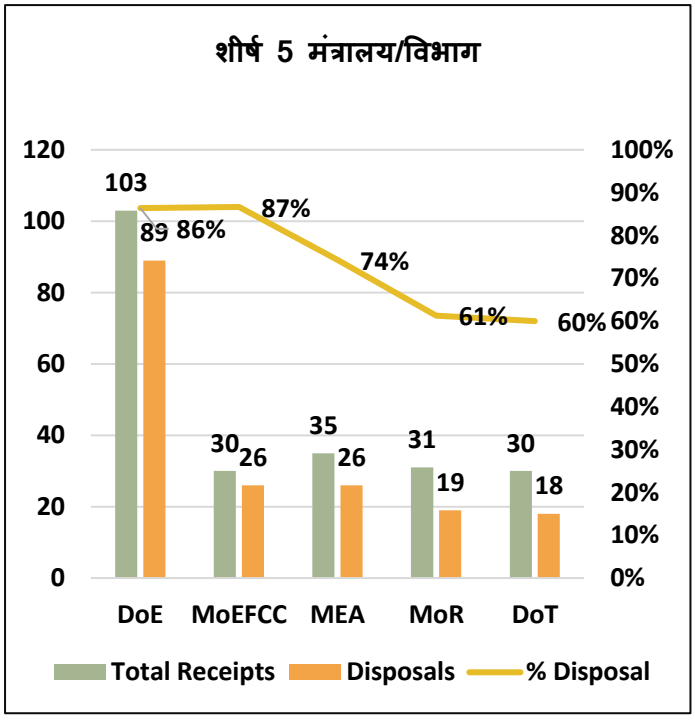

पीएमओ से प्राप्त पत्र

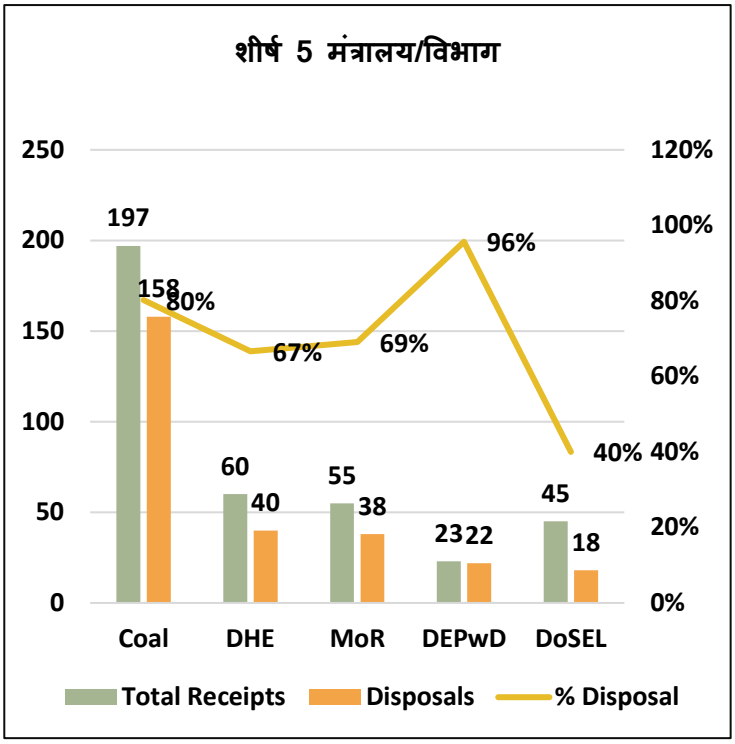

लोक शिकायतें

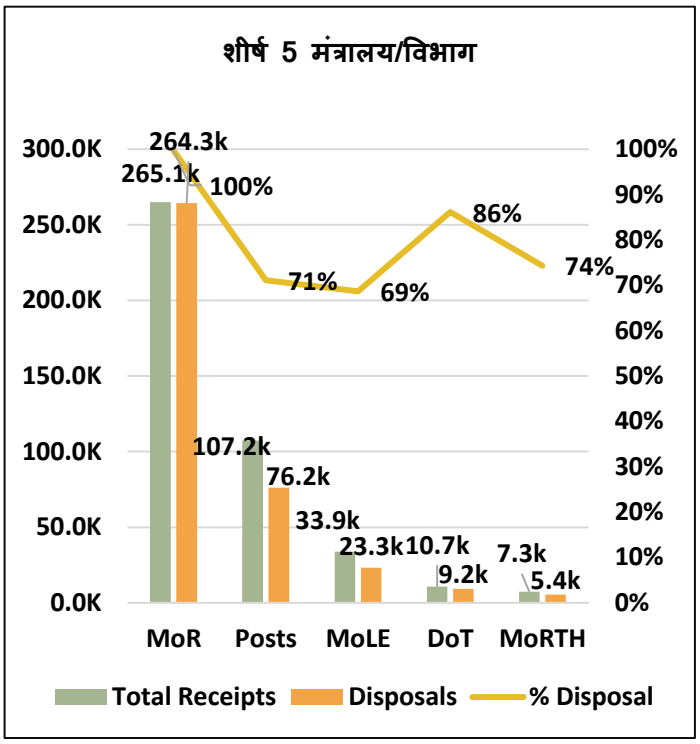

छंटाई की गई फाइलें

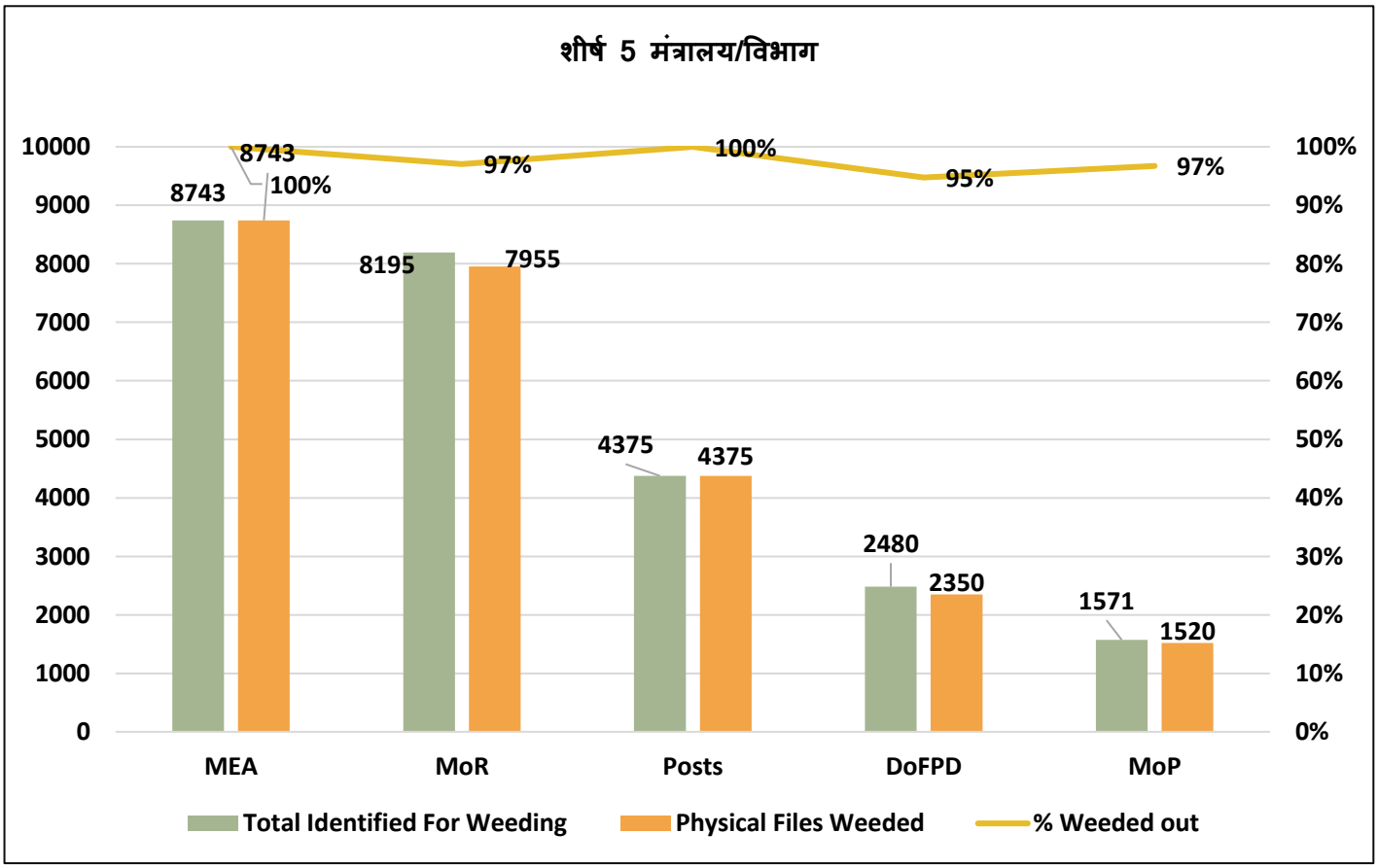

8 इन फोकस: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

परिचय

पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभाजन के बाद 2009 में बनाए गए मंत्रालय का नाम बदलकर 9 नवंबर 2020 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) कर दिया गया। यह बंदरगाहों, शिपिंग, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए, बंदरगाह क्षमता और दक्षता को निरंतर विस्तार की आवश्यकता है। उच्च लागत और जोखिमों के कारण बंदरगाह निवेश की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से सरकार की थी लेकिन संसाधन और कुशलता की बढ़ती आवश्यकताओं ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है, जिसके लिए मंत्रालय ने व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

झलकियाँ

कुशल स्थान प्रबंधन

Space freed from Scrap Disposal at SMPK

Before After

Space freed from Scrap Disposal at SMPK

Before After

Cleaning of Traffic Office at KDS, SMPK

BEFORE

एसएमपीके के विभिन्न स्क्रैप-यार्ड, स्टोर रूम आदि

स्वच्छता

पुरानी सीआईएसएफ बैरक को ध्वस्त किया गया तथा मलबे और कबाड़ को केपीएल से हटाया गया

विसर्जन के बाद नदी से मूर्तियों को हटाना (एसएमपीके)

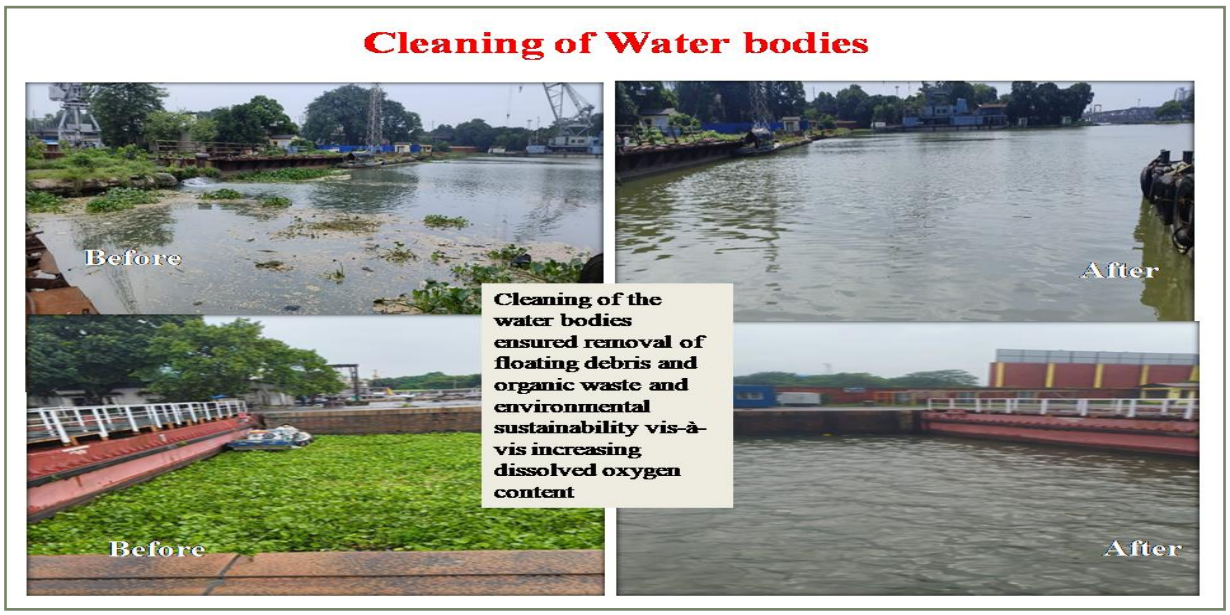

मलबे और जैविक कचरे को हटाकर जल निकायों की सफाई (एसएमपीके)

स्थानीय आबादी के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए स्वच्छ फूड स्ट्रीट का विकास

उल्लेखनीय उपलब्धियां: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)

माह	आयोजित अभियान (संख्या में)	माह में स्क्रैप निपटान/सफाई के बाद खाली की गई जगह (वर्ग फुट में)	फिजिकल फ़ाइलों की समीक्षा (संख्या में)	फ़ाइलों की छँटाई (संख्या में)	डिजिटल फ़ाइलों की समीक्षा (संख्या में)	बंद की गई फ़ाइलें (संख्या में)
जनवरी'25-जुलाई'25	90	57513	92113	56710	40063	32974

जनवरी से जुलाई, 2025 की अवधि के दौरान स्क्रैप निपटान और अर्जित राजस्व का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

माह	स्क्रैप निपटान का विवरण	अर्जित राजस्व (करोड़ रु.में)
जनवरी'25-जुलाई'25	मिश्रित स्क्रैप (कार्यालय और गैर-कार्यालय)	16.52

निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना

कैबिनेट सचिव की सिफारिशों के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संबंध में प्रस्तुतीकरण के चैनल और निपटान के अंतिम स्तर को सीएसएमओपी के अनुसार संशोधित किया गया और फाइल प्रस्तुतियों के स्तर को घटाकर अधिकतम चार कर दिया गया ।

ई-ऑफिस

ई-ऑफिस प्रणाली ने दस्तावेजों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने, रिट्रीव करने और स्टोर करने में आसानी; कागज के उपयोग में कमी, रिमोट वर्क और ऑनलाइन ऐक्सेस, बेहतर निगरानी और जवाबदेही के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। **जनवरी, 2025 से अगस्त, 2025 की अवधि के आंकड़े** नीचे दिए गए हैं:

विवरण	संख्या
एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा बनाई गई ई-फाइलों की संख्या	3000
एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा बनाई गई फिजिकल-फ़ाइलों की संख्या	38
एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा बनाई गई ई-रिसीट्स की संख्या	43260
एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा बनाई गई फिजिकल -रिसीट्स की संख्या	32

9. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर कार्यालय ज्ञापन

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
Dr. T.V. Somanathan

मंत्रिमंडल सचिव
भारत सरकार
CABINET SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D.O. No. 502/2/2/2021-CA.V

27th November, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, many initiatives have been undertaken in the recent years to make governance more responsive, accountable and transparent. The initiative for Increasing Efficiency in Decision Making, implemented since 2021, is a step in the same direction. It aims at achieving flatter and leaner organizational structures by putting in place appropriate delegation at various levels, rationalizing workload, thereby speeding up decision-making while increasing the productivity and efficiency of officers.

2. These measures have been incorporated into the Central Secretariat Manual of Office Procedure, 2022 wherein, it is emphasized that, each Ministry/Department will review the instructions on levels of disposal and channel of submission, keeping the number of levels to the minimum by delegating powers to lower formations. To facilitate quicker decision-making, the channels of submission should not be more than four.

3. However, it is observed that delayering is not being implemented in true spirit and a trend of increasing the channels of submission is observed in some Ministries/Departments. This is against the essence of the reforms undertaken so far and creates potential delays in file processing.

4. To sustain the measures undertaken as a part of Increasing Efficiency in Decision Making, you are advised to review the levels of disposal and channel of submission in your Ministry/Department and ensure that the levels do not exceed four and that the Special Secretary/ Additional Secretary/ Joint Secretary function independently as bureau heads.

5. I request you to devote your personal attention to this matter and ensure that these measures are implemented in letter and spirit, thereby fostering speedy and efficient decision making in Government.

With best wishes,

Yours sincerely,

(T.V. Somanathan)

To,

All Secretaries to Government of India

Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004
Tel.: 011-23016696, 23011241 Fax : 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in

10. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-150122/2024-O&M-DARPG (8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated: 17th December 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

It has been decided that as a sequel to the month-long Special Campaign 4.0 for Swachhata and disposal of pending matters conducted from 2nd October 2024 to 31st October 2024, the campaign has to be institutionalized and the thrust of the campaign should be maintained throughout the year. Accordingly, the following actions may be taken up by Ministries/Departments on a regular basis in order to keep the pendency to minimum possible:

(i) The system of Special Campaign Portal and Nodal Officers will continue to be operational to oversee the institutionalization / continuation of activities covered in the Special campaign.

(ii) All Ministries/Departments may dedicate 3 hours every week for continuation of activities covered in the Special campaign across all offices of Ministries/ Departments.

(iii) Nodal Officers of each Ministry may review the progress of activities on a weekly basis and the Secretary of the Ministry/ Department may review the progress on a monthly basis.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:

1. Principal Secretary to the PM
2. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi (Ms. Kavita Singh, JS)
3. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0

Copy to:

Senior Technical Director, NIC, DARPG

10. स्वच्छता को संस्थागत करने पर कार्यालय ज्ञापन

No. Q-15012/2/2024-O&M-DARPG (e-8885)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

Sardar Patel Bhawan, New Delhi
Dated 31st December, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Continuation of campaign for Swachhata and Reducing pending matters to the Minimum Possible in Government.

****

In continuation of this Department's Office Memorandum of even No. dated 17.12.2024 (copy enclosed) on the above subject it is informed that the monthly data may be reported by the Nodal Officers on the SCDPM Portal i.e. https://scdpm.nic.in. Nodal Officers can access the SCDPM portal from 3rd January, 2025 and data entry may be completed by 7th of every month.

Encl: As above.

(V. Srinivas)
Secretary to the Government of India

To

All Secretaries of the Government of India

Copy for information to:

1. All Nodal Officers of Special Campaign 4.0
2. Senior Technical Director, DARPG, NIC. — 02/01/25

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

MOST IMPORTANT

No O-16012/6/2017-ARC-DARPG (e2938)
Government of India
Ministry of Personnel Pensions and Public Grievances
Department of Administrative Reforms & Public Grievances

6th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan
Janpath, New Delhi

Dated 17th January 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: eOffice Analytics - regarding.

The undersigned is directed to say that the following guidelines may be adopted by Ministries / Departments for implementation of eOffice in Central Secretariat.

(i) Display their standing orders of delayering/Channels of Submission on their respective e-Office dashboard.

(ii) Review Virtual Private Network (VPN) usage. Non-users may be identified and steps may be taken to deactivate / close the idle account after due examination and process. The NIC teams of Ministries/Departments may approach NIC VPN Division to obtain VPN data and for deactivation of idle VPN accounts.

(iii) Follow the Manual of Office Procedure strictly and to avoid proliferation of part-files on the same subject. 'Common office function codes' as prescribed in Chapter - 6 'File Management System' of CSMOP 2022 are to be followed at the time of opening a new eFile in eOffice.

(iv) Use of Knowledge Management System (KMS) for managing the OM's, Circulars, Orders etc. and further adding them as references in eFiles. Further, a list of all files (Division-wise/bureau-wise), in PDF, may be placed in the KMS for reference of all so as to avoid creation of multiple files in the same Head or part files.

(v) Review the Designation Master in Personal Information Management System (PIMS) and identify the designations related to Personal Staff of officers. Based on the list of designations received from the Ministries / Departments, personal staff of Officers will be removed from the counts of distinct levels so that the actual distinct levels may be captured and reflected on the Analytics Dashboard.

(vi) Review and examine the Distinct Levels. Ministries/Departments may refer to 'e-File Movement Status' Report under the 'Data Analytics' tab in the e-File MIS Reports application.

Contd

11. ई-ऑफिस पर कार्यालय ज्ञापन

(vii) Review the Basic File Head and notify the standardized Heads based on the relevant subjects of the Ministry/Department. Based on the list of Heads received from the Ministries/Departments, a consolidated list of Heads will be prepared which may be considered as standard Subjects to fetch the Subject-wise pendency.

(viii) The Ministries/Departments who process statutory clearance for various projects such as Ministry of Environment, Forest and Climate Change may provide expected time for clearance, so that the processing time of such files may be noticed.

(ix) E-Office Analytics to be developed to indicate file pendency at each level, to identify time delays and pendency. Emphasis to be given to identifying subject specific pendency across Ministries/Departments.

2. This issues with the approval of Secretary, DARPG.

सुनील सिंह

(Sunil K. Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.011-23440371
email: sunilk.singh73@nic.in

To

Secretaries to the Govt. of India

Copy to:

1. DG, NIC
2. Shri M.K. Mishra, DDG, NIC email: mk.mishra@nic.in
3. Shri Kapil Kumar Sharma, Sr. Director (IT), NIC
4. eOffice-PMU, NIC

Copy for information to:

PSO to Secy. (AR&PG)/PA to JS (SC) /DS (eOffice)

अनुलग्नक I: अपलोड नहीं किए गए आँकड़े

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
1	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
3	राजभाषा विभाग
4	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
5	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
6	औषध विभाग
7	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
8	युवा कार्यक्रम विभाग
9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
10	गृह मंत्रालय
11	खान मंत्रालय
12	जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक II- संक्षेपाक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर)
2.	सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
3.	डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
4.	डीएआरपीजी	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
6.	डीए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
7.	डीएएच	पशुपालन, डेयरी विभाग
8.	डीएई	परमाणु ऊर्जा विभाग
9.	डीबीटी	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
10.	डीसीपी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
11.	डीओसी	वाणिज्य विभाग
12.	डीओसीए	उपभोक्ता मामले विभाग
13.	डीओडी	रक्षा विभाग
14.	डीओडीपी	रक्षा उत्पादन विभाग
15.	डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
16.	एमओ डीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
17.	डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
18.	डीईपीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
19.	डीईएक्सडब्ल्यू	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
20.	डीओई	व्यय विभाग
21.	डीओएफ	उर्वरक विभाग
22.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
23.	फिशरीज	मत्स्य पालन विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
24.	डीओएफपीडी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
25.	डीएच एंड एफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
26.	डीएचआर	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27.	डीएचई	उच्चतर शिक्षा विभाग
28.	दीपम	विनिवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
29.	डीओजे	न्याय विभाग
30.	डीओएलआर	भूमि संसाधन विभाग
31.	डीओएलए	विधि कार्य विभाग
32.	डीएमए	सैन्य कार्य विभाग
33.	डीओएल	राजभाषा विभाग
34.	डीपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
35.	डीओपीटी	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
36.	डीओपीएच	औषध विभाग
37.	पोस्ट्स	डाक विभाग
38.	डीओपीई	लोक उद्यम विभाग
39.	डीओआर	राजस्व विभाग
40.	डीओआरडी	ग्रामीण विकास विभाग
41.	डीओएसईएल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
42.	डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
43.	डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
44.	डीओएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
45.	डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
46.	स्पोर्ट्स	खेल विभाग
47.	डीओटी	दूरसंचार विभाग
48.	डीओडब्ल्यूआर एंड आरडी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
49.	डीओवाईए	युवा कार्यक्रम विभाग
50.	एलडी	विधायी विभाग
51.	आयुष	आयुष मंत्रालय
52.	एमओसीए	नागर विमानन मंत्रालय
53.	कोल	कोयला मंत्रालय
54.	को-ऑपरेशन	सहकारिता मंत्रालय
55.	एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
56.	एमओसी	संस्कृति मंत्रालय
57.	डीओडीडब्ल्यूएस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
58.	एमओई	शिक्षा मंत्रालय
59.	एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
60.		इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
61.	एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
62.	एमईए	विदेश मंत्रालय
63.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
64.	एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
65.	एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
66.	एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
67.	एमएचए	गृह मंत्रालय
68.	एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
69.	एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
70.	एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
71.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
72.	एमओएम	खान मंत्रालय
73.	एमओएएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
74.	एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क्र. सं.	संक्षेपाक्षर	मंत्रालय/विभाग का नाम
75.	एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
76.	एमपीए	संसदीय कार्य मंत्रालय
77.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
78.	एमओपी	विद्युत मंत्रालय
79.	एमओआर	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
80.	एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
81.	एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
82.	एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
83.	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
84.	एमओएस	इस्पात मंत्रालय
85.	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय
86.	टूरिज़्म	पर्यटन मंत्रालय
87.	एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
88.	एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
89.	एमओवाईएस	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
90.	नीति आयोग	नीति आयोग

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

भारत सरकार

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001